पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस के संबंध में राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी की धनराशि निम्नवत् है:-

राज्य	वर्ष		(करोड़ रुपए)
	1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
गुजरात	23.91	29.12	29.75
असम	4.51	3.51	3.11
त्रिपुरा	0.69	0.61	0.58
तमिलनाडु	0.31	0.32	0.23
आन्ध्र प्रदेश	6.89	8.30	8.31
राजस्थान	—	—	0.01

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of SKO/LDO/RO/LPG Dealerships to the Relatives of the Members of OSB

425. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the relatives of members of OSB's are given priority during the selection of dealers/distributors of Indian Oil Corporations; and

(b) if so, how many SKO/LDO dealerships/R.O. dealerships and LPG distributorships have been allotted to the relatives of members of OSB's of different States during the last three years under discretionary quota and by the OSB's?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) No, Sir.

(b) Relationship of a candidate with any Member of OSBs or any other authorities is not a criterion for allotment of dealerships/distributorships either on compassionate grounds or through normal selection procedure. Therefore, such information is not maintained.

Eviction of Tribals from West Godavari

426. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of India have given instructions to the Forest Department in Andhra Pradesh to evict tribals living in Sunnalbandi village in Polavaram Mandal of West Godavari District;

(c) To increase the forest cover in the country as well as in Bihar, the following Centrally Sponsored Schemes are already in operation:—

1. Integrated Afforestation and Eco-Development Projects.
2. Area Oriented Fuelwood & Fodder Projects.
3. Conservation and Development of Non-Timber Forest produce including Medicinal plants.

and moisture conservation, promotion of fuelwood saving devices, awareness building, extension of new technologies and treatment of special problem lands are taken up in degraded forest watersheds. 3 projects have been sanctioned under this scheme for Bihar in the districts of Dhanbad, Palamau and Hazaribagh, with a total outlay of Rs. 6.35 crores.

(b) if so, the details of this advisory;

(c) whether Government are aware that the tribals of Sunnalbandi have been living there for a minimum of 2 centuries; and

(d) what steps would be taken to stay and stop such advice of eviction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

मध्य प्रदेश में डाकघरों के लिए नए भवन

427. **श्री अजीत जोगी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में इस समय कितने डाकघरों के पास विभाग के भवन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कुछ नए भवनों का निर्माण करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है और वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) मध्य प्रदेश में 1185 डाकघर विभागीय भवनों में नहीं हैं।

(ख) धनराशि का अभाव होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल विभाग का निजीकरण

428. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे के कुछ विभागों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो क्या यह निर्णय विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में लिया गया है;

(ख) क्या इसी योजना के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों की छंटनी भी की गई है;

(ग) क्या विभिन्न रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इसके खिलाफ कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया है; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफ़र शरीफ): (क) से (घ) जी नहीं, रेलवे का अपने विभागों में से किसी विभाग का निजीकरण करने का प्रस्ताव नहीं है, केवल कतिपय आफ लाइन गतिविधियां, जो रेल परिचालनों से प्रत्यक्षतः नहीं जुड़ी है, निजी क्षेत्र को दी जानी है। यह विनिश्चय किसी बाहरी एजेंसी के दबाव में आए बिना आंतरिक रूप से किया गया है।

कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजीकरण के मुद्दे पर कर्मचारियों के विभिन्न मंचों से सुझाव प्राप्त हुए हैं, इनका संतोषजनक ढंग से उत्तर दे दिया गया है।

दिल्ली में वृद्ध दम्पतियों और महिलाओं की हत्या के मामले

429. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान और 15 जुलाई, 1995 तक राष्ट्रीय राजधानी में हत्या, अपहरण और बलात्कार की अलग-अलग थाना-वार कुल कितनी-कितनी घटनाएं हुई;

(ख) उपरोक्त हत्याओं इत्यादि की घटनाओं में से वृद्ध दम्पतियों की हत्या और लूट की घटनाओं का थाना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हत्याओं के कितने मामलों में महिलाएं अपने पतियों / रिश्तेदारों द्वारा जलाकर अथवा अन्य तरीकों से मार डाली गई;

(घ) कितने अपहृत लोगों को रिहा करवाया जा सका और कितने लोगों की हत्या कर दी गई थी; और

(ङ) अपहरण की कितनी घटनाएं फिरौती के लिए हुई और पुलिसकर्मियों की अंतर्ग्रस्तता वाली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) सूचना संलग्न अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 174, अनुपत्र सं॰-16]